Shortage of drinkign water in villages of Saurashtra and Kachh

3991. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:

SHRI ANANTHAY DEVSHANKER DAVE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that there was an acute shortag of drinking water in the villages of Saurashtra and Kachh due to severe drought;

(b) if so, what measures have been taken by Government to provide drinking water in those villages in the State;

(c) whether Government have provided extra amount to the State Government for the purpose of providing water to more villages of this region;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) if not, what measures Government propse to take to provide drinking water to the people of Saurashtra-Kachh region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): Yes, Sir.

(b) Master Plan amouting to Rs. 20.67 crores had been prepared by the State Government to overcome the drniking water problem. 3413 villages had been supplied with safe drinking water by various schemes during the scarcity year 1993-94 (October, 1993 to September, 1994).

(c) to (e) During 1994-95 an amount of As. 31.875 crores was released in advance to the State Government of Gujarat out of the Central share of Calamity Relief Fund to tide over the problem in the drought affected areas including drinking water supply.

गुजरात के ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र में बेरोजगारी तथा पिछड़ेपन की समस्याएं

3992. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के विशेषत: बड़ोदरा, भडौच, सूरत, अहमदाबाद तथा पंचमहल जिलों के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त जिलों में इस संबंध में कोई व्यापक सर्वेक्षण करवाया गया है , और

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त योजना के लिये केन्द्रीय सहायता की कोई धनराशि निर्धारित की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई ह. पटेल) : (क) और (ख) गजरात सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्याओं का समाधान करने के लिये भारत सरकार कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात् (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) सुनिश्चित रोजगार योजना, (4) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और (5) मरूभूमि विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है ।

(1) **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम का लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण

परिवारों को सरकारी सबसिडी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ग्रुप की मार्फत उनकी आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियां मुहैया कराके उनको पारिवारिक आय में वृद्धि करना है। इस कार्यक्रम को गुजरात के बड़ोदरा, भड़ौच, सूरत, अहमदाबाद और पंचमहल जिलों सहित देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना का वित्त-पोषण केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(2) **जवाहर रोजगार योजना:** यह योजना ग्रामीण गरीबों को स्थायी रोजगार मुहैया कराने के लिये 1989–90 से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत निधियों को केन्द्र और राज्य के बीच 80:20 के अनुपात में वहन किया जाता है। इस योजना को 1993–94 से देश के 120 चयनित पिछड़े जिलों में गहन किया गया है। गुजरात में गहन जवाहर रोजगार योजना बडोदरा, सूरत और पंचमहल जिलों सहित 6 जिलों में कार्यरत हैं।

(3) **सुनिश्चित रोजगार योजना :** यह योजना 1993–94 में देश के उन खंडों में शुरू की गई थी जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है। योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से सक्षम सभी व्यक्तियों, जिन्हें कार्य की जरूरत है और जो इसे चाहते हैं, को 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है। 1993–94 में यह योजना गुजरात के 16 जिलों के 97 खंडों में चलाई जा रही थी। 1994–95 में इस योजना का राज्य के 10 जिलों के 38 अतिरिक्त खंडों में विस्तार किया गया है।

(4) **सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं विकास द्वारा फसलों, पशुधन और मानव संसाधनों के उत्पादन पर सूखा के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। यह कार्यक्रम अहमदाबाद और पंचमहल जिलों सहित गुजरात के 8 जिलों के चयनित 43 सूखाग्रस्त खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का वित्त-पोषण केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(5) **मरूभूमि विकास कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरूस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण पाना और भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। कार्यक्रम का शत-प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र द्वारा किया जाता है। फिलहाल, यह कार्यक्रम गुजरात के 2 जिलों के 9 खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा सहायता के लिये पात्र निर्धन परिवारों का पता लगाने के लिये प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पूर्व एक व्यापक सर्वेक्षण करवाया जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की क्षमताओं और कमजोरियों का पता लगाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा समवर्ती मूल्यांकन के रूप में गहन अध्ययन भी कराये गये हैं।

(घ) विवरण में दिये गये विवरण के अनुसार।

विवरण

रोजगार सृजन और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए 1994–95 के दौरान से गुजरात में चयनितजिलों को केन्द्रीय रिलीज

(रुपए लाख में)

जिला	जवाहर रोजगार योजना	गहन जवाहर रोजगार योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	मरूभूमि विकास कार्यक्रम
1. बड़ोदरा	574.77	268.00	160.00	125.78	—	—
2. भड़ौच	466.74	—	260.00	109.81	—	—
3. सूरत	683.27	298.00	260.00	139.36	—	—
4. अहमदाबाद	218.39	—	40.00	67.29	30.50	—
5. पंचमहल	1783.31	476.00	440.00	214.41	100.75	—
समग्र गुजरात	8268.65	2067.50	3580.00	1507.63	617.35	441.55

Scheme of rural development funded by Central/State government

3993. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the schemes under Rural Development which are 100 per cent funded by Central Government;

(b) what are the schemes under Rural Development funded jointly by the State Governments and Central Government;

(c) what is the allocation under 100 per cent scheme to Karnataka during 1992-93, 1993-94 and 1994-95 and the allocation during this period for jointly funded schemes; the details thereof schemes-wise; and

(d) whether the State Government have deviated the funds to meet their expenditure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Under Rural Development Schemes, Desert Development Programme (DDP) is 100 per cent funded by the Central Government.

(b) (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP), (ii) Jawarhar Rozgar Yojana (JRY), (iii) Employment Assurance Scheme (EAS), (iv) Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) and (v) Drought Prone Area Programme (DDAP) are major Rural Development Programmes jointly funded by the States and Central Government. Under IRDP and DPAP the funding pattern between Centre and the State is 50:50 and for JRY & EAS it is 80:20. Under ARWSP the funds are provided 100 per cent by the Centre subject to matching by the States under MNP.